



Exam Genius

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam



BANKING AND FINANCIAL AWARENESS

15 - 21 FEB 2026

3RD WEEK OF FEBRUARY

50+ MCQ
with detailed
explanation



- Banking & finance
- Banking Facilities
- Banking Appointment
- Banking Agreement



Ques: As per RBI's draft directions, what action must banks take if mis-selling is established?

RBI के ड्राफ्ट निर्देशों के अनुसार, यदि गलत बिक्री (Mis-selling) साबित होती है तो बैंक को क्या करना होगा?

- A) Issue warning to employee only / केवल कर्मचारी को चेतावनी देना
- B) Pay 10% penalty to RBI / RBI को 10% जुर्माना देना
- C) Refund full amount and compensate for loss / पूरी राशि वापस करना और नुकसान की भरपाई करना
- D) Close customer's account / ग्राहक का खाता बंद करना
- E) No action required / कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has issued comprehensive draft directions on advertising, marketing, and sales of financial products and services by banks.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों द्वारा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापन, विपणन और बिक्री से संबंधित व्यापक ड्राफ्ट निर्देश जारी किए हैं।
- The objective of these directions is to prevent mis-selling and compulsory bundling of financial products.
- इन निर्देशों का उद्देश्य गलत बिक्री (Mis-selling) और जबरन बंडलिंग को रोकना है।
- As per the Draft RBI (Commercial Banks – Responsible Business Conduct) Amendment Directions, 2026, banks must seek customer feedback within 30 days of sale.
- ड्राफ्ट RBI (वाणिज्यिक बैंक – जिम्मेदार व्यवसाय आचरण) संशोधन निर्देश, 2026 के अनुसार, बैंकों को बिक्री के 30 दिनों के भीतर ग्राहक से फीडबैक लेना अनिवार्य होगा।
- The new directions are scheduled to come into effect from July 1.
- ये नए निर्देश 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
- If mis-selling is established, banks must refund the entire amount paid by the customer.
- यदि गलत बिक्री साबित होती है, तो बैंक को ग्राहक द्वारा चुकाई गई पूरी राशि वापस

करनी होगी।

- In addition, banks must compensate customers for any financial loss arising due to mis-selling.
- इसके अलावा, गलत बिक्री के कारण हुए किसी भी वित्तीय नुकसान की क्षतिपूर्ति भी बैंकों को करनी होगी।
- These provisions aim to strengthen consumer protection and responsible business conduct in the banking sector.
- ये प्रावधान बैंकिंग क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण और जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण को मजबूत करने के लिए लाए गए हैं।

Ques: Which international financial institution approved a USD 182 million loan to Assam to strengthen resilience against flooding and riverbank erosion?

असम में बाढ़ और नदी तट कटाव से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने स्वीकृत किया?

- A) World Bank / विश्व बैंक
- B) International Monetary Fund (IMF) / अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- C) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) / एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
- D) Asian Development Bank (ADB) / एशियन डेवलपमेंट बैंक
- E) New Development Bank (NDB) / न्यू डेवलपमेंट बैंक

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The Asian Development Bank (ADB) approved a USD 182 million loan to Assam.
- एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने असम को 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है।

- Objective: To expand support for strengthening Assam's resilience to chronic flooding and severe riverbank erosion along the Brahmaputra River.
- उद्देश्य: ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लगातार बाढ़ और गंभीर नदी तट कटाव से निपटने की असम की क्षमता को मजबूत करना।
- ADB supports **sustainable, inclusive, and resilient development** across Asia and the Pacific.
- ADB एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सतत, समावेशी और लचीले विकास को समर्थन देता है।

About Asian Development Bank :

- Established : 19 December 1966
- HQ : Manila, Philippines
- Members : 69
- Chief Economist : Albert Park
- President : Masato Kanda

Ques: Which two institutions signed an MoU to deepen financial inclusion by providing access to mutual fund products in rural and semi-urban areas?

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड उत्पादों की पहुँच बढ़ाने के लिए किन दो संस्थानों ने समझौता (MoU) किया है?

- A) Department of Posts and BSE / डाक विभाग और बीएसई
- B) Department of Posts and NSE / डाक विभाग और एनएसई
- C) RBI and NSE / आरबीआई और एनएसई
- D) SEBI and India Post Payments Bank / सेबी और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
- E) LIC and NSE / एलआईसी और एनएसई

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Department of Posts, Ministry of Communications, and the National

Stock Exchange of India Limited (**NSE**) signed a Memorandum of Understanding (MoU) to deepen financial inclusion.

• संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (**NSE**) ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता (MoU) किया है।

• The initiative aims to provide **access to mutual fund products in rural and semi-urban areas.**

• इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड उत्पादों की पहुँच सुनिश्चित करना है।

• The partnership will leverage **India Post's vast network of over 1.64 lakh post offices** across the country.

• इस साझेदारी में इंडिया पोस्ट के **1.64 लाख से अधिक डाकघरों के व्यापक नेटवर्क का उपयोग** किया जाएगा।

• The objective is to promote **transparency, investor literacy, and participation in capital market-linked products.**

• इसका उद्देश्य पारदर्शिता, निवेशक साक्षरता और पूंजी बाजार से जुड़े उत्पादों में **भागीदारी को बढ़ावा देना** है।

• The MoU is **valid for three years** and can be renewed by mutual consent of both parties.

• यह समझौता **तीन वर्षों के लिए वैध है** और आपसी सहमति से नवीनीकृत किया जा सकता है।

National Stock Exchange :

- Established : 1992 (Commenced operations in 1994)
- HQ : Mumbai, Maharashtra
- MD & CEO : Ashishkumar Chauhan (Current as of 2026)

Ques: What was the value of the RBI Digital Payments Index (RBI-DPI) for September 2025?

सितंबर 2025 के लिए RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स (RBI-DPI) का मान क्या था?

- A) 493.22
- B) 465.33
- C) 516.76
- D) 445.50
- E) 395.57

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Reserve Bank of India (RBI) has been publishing the **RBI-Digital Payments Index (RBI-DPI)** since **1 January 2021**, with **March 2018** as the base year (Index = 100).
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) **1 जनवरी 2021** से **RBI-डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स (RBI-DPI)** प्रकाशित कर रहा है, जिसका आधार वर्ष **मार्च 2018 (इंडेक्स = 100)** है।
- The **RBI-DPI for September 2025 stood at 516.76**, rising from **493.22** in **March 2025**.
- **सितंबर 2025 में RBI-DPI 516.76** रहा, जो **मार्च 2025 के 493.22** से अधिक है।
- This increase reflects **significant growth in digital payment adoption and performance** across India.
- यह वृद्धि देशभर में **डिजिटल भुगतान के उपयोग और प्रदर्शन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी** को दर्शाती है।
- RBI-DPI measures the **extent and depth of digitisation of payments over time**.
- RBI-DPI **समय के साथ डिजिटल भुगतान के विस्तार और गहराई को मापता है।**
- The index is based on **five broad parameters with assigned weights**:
- यह इंडेक्स **पाँच व्यापक मानकों और उनके निर्धारित भार पर आधारित है:**
 - **Payment Enablers – 25%** / पेमेंट एनेबलर्स – 25%
 - **Payment Infrastructure (Demand-side) – 10%** / पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर (डिमांड

साइड) – 10%

– Payment Infrastructure (Supply-side) – 15% / पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर (सप्लाई साइड)
– 15%

– Payment Performance – 45% / पेमेंट परफॉर्मेंस – 45%

– Consumer Centricity – 5% / कंज्यूमर सेंट्रिसिटी – 5%

Ques: What major regulatory change has the RBI introduced for Real Estate Investment Trusts (REITs)?

रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) के लिए RBI ने कौन-सा महत्वपूर्ण नियामकीय बदलाव किया है?

A) RBI has allowed foreign banks to directly own REITs / RBI ने विदेशी बैंकों को REITs का प्रत्यक्ष स्वामित्व लेने की अनुमति दी है

B) RBI has permitted banks to lend directly to REITs with prudential safeguards / RBI ने सावधानीपूर्ण सुरक्षा उपायों के साथ बैंकों को REITs को सीधे ऋण देने की अनुमति दी है

C) RBI has removed listing requirements for REITs / RBI ने REITs के लिए लिस्टिंग आवश्यकताएँ समाप्त कर दी हैं

D) RBI has merged REIT regulations with mutual fund norms / RBI ने REIT नियमों को म्यूचुअल फंड नियमों के साथ विलय कर दिया है

E) RBI has restricted REIT funding only to NBFCs / RBI ने REIT फंडिंग को केवल NBFCs तक सीमित कर दिया है

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has allowed banks to lend directly to Real Estate Investment Trusts (REITs) with prudential safeguards.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सावधानीपूर्ण सुरक्षा उपायों के साथ बैंकों को REITs को

सीधे ऋण देने की अनुमति दी है।

- This move aims to deepen credit access for the real estate sector and address long-term funding needs.

- इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ाना और दीर्घकालिक फंडिंग की समस्या को हल करना है।

- Earlier, banks were barred from lending to REITs, though lending to Infrastructure Investment Trusts (InvITs) was permitted.

- पहले बैंकों को REITs को ऋण देने की अनुमति नहीं थी, जबकि InvITs को ऋण देना अनुमत था।

- Existing InvIT lending norms will now be harmonised with safeguards applicable to REITs.

- मौजूदा InvIT ऋण मानदंडों को अब REIT सुरक्षा उपायों के अनुरूप बनाया जाएगा।

- Currently, India has five listed REITs:

- Brookfield India Real Estate Trust

- Embassy Office Parks REIT

- Mindspace Business Parks REIT

- Nexus Select Trust

- Knowledge Realty Trust

- Earlier, REITs largely relied on short-term bonds (3–5 years) subscribed by mutual funds, NBFCs, and others, leading to long-term funding challenges.

- पहले REITs मुख्यतः अल्पकालिक बॉन्ड (3–5 वर्ष) पर निर्भर थे, जिससे दीर्घकालिक वित्तपोषण की समस्या उत्पन्न होती थी।

Ques: Which organisations signed an agreement to enable UPI-based cross-border merchant payments between India and Malaysia?

भारत और मलेशिया के बीच UPI-आधारित क्रॉस-बॉर्डर मर्चेंट भुगतान सक्षम करने के लिए किन संगठनों ने समझौता किया?

A) RBI and Bank Negara Malaysia / आरबीआई और बैंक नेगारा मलेशिया

B) NPCI and Maybank / NPCI और मेबैंक

C) NPCI International Payments Limited and Payments Network Malaysia

- (PayNet) / NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और पेमेंट्स नेटवर्क मलेशिया (PayNet)
- D) SEBI and CIMB Bank / सेबी और सीआईएमबी बैंक
- E) SBI and RHB Bank / एसबीआई और आरएचबी बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- NPCI International Payments Limited (NIPL) has signed an agreement with Payments Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet).
- NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने पेमेंट्स नेटवर्क मलेशिया Sdn Bhd (PayNet) के साथ समझौता किया है।
- The agreement aims to enable QR-based cross-border merchant payments between India and Malaysia.
- यह समझौता भारत और मलेशिया के बीच QR-आधारित क्रॉस-बॉर्डर मर्चेन्ट भुगतान को सक्षम बनाने के लिए है।
- In the first phase, Indian travellers visiting Malaysia can scan DuitNow QR codes using Unified Payments Interface (UPI) enabled apps.
- पहले चरण में, मलेशिया जाने वाले भारतीय यात्री UPI-सक्षम ऐप्स से DuitNow QR को स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे।
- This will allow seamless merchant payments directly through UPI apps at DuitNow QR acceptance points.
- इससे DuitNow QR स्वीकार करने वाले व्यापारियों को सीधे UPI ऐप के माध्यम से सहज भुगतान संभव होगा।
- The move strengthens India's global digital payments footprint and promotes UPI as a cross-border payment solution.
- यह कदम वैश्विक स्तर पर भारत के डिजिटल भुगतान प्रभाव को मजबूत करता है और UPI को क्रॉस-बॉर्डर भुगतान समाधान के रूप में बढ़ावा देता है।

Ques: Which two institutions signed an agreement to enable cashless Ayurveda treatment under general health insurance in India?

भारत में सामान्य स्वास्थ्य बीमा के तहत कैशलेस आयुर्वेद उपचार सक्षम करने के लिए किन दो संस्थानों ने समझौता किया?

- A) Ministry of AYUSH and IRDAI / आयुष मंत्रालय और IRDAI
- B) AIIMS New Delhi and General Insurance Council / एम्स नई दिल्ली और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल
- C) AIIA New Delhi and General Insurance Council / अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) नई दिल्ली और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल
- D) NITI Aayog and LIC / नीति आयोग और एलआईसी
- E) National Health Authority and GIC / राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और GIC

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- All India Institute of Ayurveda (AIIA), New Delhi and the General Insurance Council (GIC) signed an agreement to integrate Ayurveda into India's mainstream health insurance ecosystem.
- अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA), नई दिल्ली और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (GIC) ने आयुर्वेद को भारत की मुख्यधारा स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था में शामिल करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- The agreement enables cashless treatment facilities for eligible Ayurveda-based healthcare services across all 32 general insurance companies in India.
- इस समझौते के तहत देश की सभी 32 सामान्य बीमा कंपनियों में पात्र आयुर्वेद आधारित उपचारों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध होगी।
- This move is a major step toward mainstreaming traditional medicine and improving patient access to alternative healthcare systems.
- यह पहल पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को मुख्यधारा में लाने और रोगियों की पहुँच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- AYUSH stands for Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha, and Homoeopathy.

- AYUSH का अर्थ है – आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी।
- The Ministry of AYUSH was established on 9 November 2014 to promote education, research, and development of India's traditional systems of medicine.
- आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के विकास, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- For the first time, the Government of India(GoI) has launched a dedicated Ayush Health Insurance Helpline '1800-11-0008' to support beneficiaries
- भारत सरकार ने पहली बार आयुष स्वास्थ्य बीमा के लाभार्थियों की सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन '1800-11-0008' शुरू की है।

About All India Institute of Ayurveda :

- Established : 2015
- HQ : New Delhi
- Director : Pradeep Kumar Prajapati

About General Insurance Council :

- Established : 1957
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Tapan Kumar Singhel

Ques: As per the February 2026 draft guidelines, what Credit-Deposit (CD) ratio target has been set for rural and semi-urban branches under the Lead Bank Scheme (LBS)?

फरवरी 2026 के मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार लीड बैंक स्कीम (LBS) के तहत ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के लिए CD रेशियो लक्ष्य क्या है?

- A) 40%
- B) 50%

- C) 60%
- D) 70%
- E) 80%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या :

- Reserve Bank of India (RBI) issued draft guidelines in **February 2026** to streamline the **Lead Bank Scheme (LBS)** with a focus on improving credit flow in rural and semi-urban areas.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने फरवरी 2026 में लीड बैंक स्कीम (LBS) को सुव्यवस्थित करने के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए।
- As per the draft, **rural and semi-urban branches must achieve a minimum CD ratio of 60%**.
- मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं को न्यूनतम 60% CD रेशियो हासिल करना होगा।
- The **Credit-Deposit (CD) ratio** indicates how much of the deposits mobilised by banks are converted into loans; a higher ratio reflects better local credit deployment.
- **क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) रेशियो** यह दर्शाता है कि बैंकों द्वारा जुटाई गई जमा राशि का कितना हिस्सा ऋण के रूप में दिया गया है; अधिक CD रेशियो बेहतर स्थानीय ऋण प्रवाह को दर्शाता है।
- **District Consultative Committees (DCCs)** will closely monitor districts where the CD ratio lies between **40% and 60%** to improve performance.
- जिन जिलों में CD रेशियो 40% से 60% के बीच है, उनकी निगरानी **जिला परामर्श समिति (DCC)** द्वारा की जाएगी।
- Districts with a **CD ratio below 20%** will be classified as **'Special Category' districts**, indicating very low credit absorption.
- **20% से कम CD रेशियो** वाले जिलों को **'विशेष श्रेणी'** में रखा जाएगा।
- The guidelines also mandate that **at least 25% of total banking outlets** be opened in **Tier-V and Tier-VI Under-Served Rural Centres (URCs)** to strengthen financial inclusion.
- इसके अलावा **टियर-V और टियर-VI अंडर-सर्व्ड रूरल सेंटर्स (URCs)** में **कम-से-कम**

25% बैंकिंग आउटलेट खोलने का प्रावधान किया गया है।

- Overall, the objective is to **deepen financial inclusion** and **improve credit flow to priority sectors** such as agriculture and MSMEs.
- समग्र रूप से, इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को गहरा करना और प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाना है।

Ques: Who has received a three-year extension as the Managing Director & CEO of AU Small Finance Bank?

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे तीन वर्ष का विस्तार मिला है?

- A) Uday Kotak / उदय कोटक
- B) **Sanjay Agarwal / संजय अग्रवाल**
- C) Hasmukh Adhia / हसमुख अधिया
- D) Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
- E) Chandra Shekhar Ghosh / चंद्रशेखर घोष

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- AU Small Finance Bank announced that Reserve Bank of India (**RBI**) has approved the reappointment of Sanjay Agarwal as its Managing Director & Chief Executive Officer.
- एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक (**RBI**) ने संजय अग्रवाल की एमडी एवं सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है।
- The extension is for a **further period of three years**, effective from **April 19**.
- यह विस्तार **19 अप्रैल** से प्रभावी **तीन वर्षों** के लिए है।
- The reappointment had earlier been approved by the **Board (October 17, 2025)** and **shareholders (December 26, 2025)**, subject to RBI confirmation.
- पुनर्नियुक्ति को पहले **बोर्ड (17 अक्टूबर 2025)** और **शेयरधारकों (26 दिसंबर 2025)** से

मंजूरी मिल चुकी थी, जो RBI की पुष्टि के अधीन थी।

- Recently, **AU Small Finance Bank** also received **in-principle approval from RBI** to transition into a **universal bank**.

- हाल ही में **एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक** को **यूनिवर्सल बैंक** में परिवर्तित होने के लिए **RBI** से **सैद्धांतिक मंजूरी** भी प्राप्त हुई है।

Ques: As per the revised norms, what is the maximum aggregate exposure banks can extend towards acquisition (M&A) financing?

संशोधित मानदंडों के अनुसार, बैंक अधिग्रहण (M&A) फाइनेंसिंग के लिए अधिकतम कितना कुल एक्सपोजर दे सकते हैं?

- A) 10% of capital base / पूंजी आधार का 10%
- B) 15% of capital base / पूंजी आधार का 15%
- C) **20% of capital base / पूंजी आधार का 20%**
- D) 25% of capital base / पूंजी आधार का 25%
- E) 30% of capital base / पूंजी आधार का 30%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Reserve Bank of India (**RBI**) has allowed banks to extend aggregate exposure up to **20% of their eligible capital base** for acquisition (M&A) financing, increased from the earlier proposed **10%**.

- **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** ने अधिग्रहण फाइनेंसिंग के लिए बैंकों को अपनी पात्र पूंजी आधार का **20%** तक कुल एक्सपोजर देने की अनुमति दी है, जो पहले प्रस्तावित **10%** था।

- Banks are now permitted to finance **acquisitions of unlisted companies**, subject to prescribed conditions.

- अब बैंकों को कुछ शर्तों के तहत **अनलिस्टेड कंपनियों के अधिग्रहण** के लिए फाइनेंसिंग

की अनुमति दी गई है।

- The target unlisted company must have a **minimum net worth of ₹500 crore**, be **profit-making for the last three years**, and possess an **investment-grade credit rating (BBB– or above)**.
- लक्षित अनलिस्टेड कंपनी की **न्यूनतम नेटवर्थ ₹500 करोड़**, पिछले तीन वर्षों से लाभ में होना, और **निवेश-ग्रेड रेटिंग (BBB– या उससे ऊपर)** होना अनिवार्य है।
- The permissible portion of bank financing has been increased to **75% of the acquisition value** from the earlier proposed **70%**.
- बैंक फाइनेंसिंग की अनुमत सीमा को पहले प्रस्तावित **70%** से बढ़ाकर **अधिग्रहण मूल्य का 75%** कर दिया गया है।
- The remaining **25%** of the acquisition cost must be funded by the acquirer through **internal accruals or fresh equity issuance**.
- शेष **25%** राशि अधिग्रहणकर्ता को **आंतरिक संसाधनों या नई इक्विटी जारी कर जुटानी** होगी।
- These revisions aim to provide **greater flexibility to banks** while ensuring **prudent risk management** in acquisition financing.
- इन संशोधनों का उद्देश्य **संतुलित जोखिम प्रबंधन** बनाए रखते हुए बैंकों को **अधिक लचीलापन** प्रदान करना है।

Ques: Who has been appointed as the Chairman of GIFT City by the Government of Gujarat?

गुजरात सरकार द्वारा गिफ्ट सिटी के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Hasmukh Adhia / हसमुख अधिया
- B) Uday Kotak / उदय कोटक
- C) Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
- D) Rajeev Jain / राजीव जैन
- E) Ajay Seth / अजय सेठ

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Government of Gujarat appointed Uday Kotak as the Chairman of Gujarat International Finance Tec-City Company Ltd (**GIFT City**).
- गुजरात सरकार ने उदय कोटक को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कंपनी लिमिटेड (**GIFT City**) का चेयरमैन नियुक्त किया।
- Uday Kotak is the **Founder and Director** of Kotak Mahindra Bank.
- वे कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक एवं निदेशक हैं।
- He replaced Hasmukh Adhia in this position.
- उन्होंने इस पद पर हसमुख अधिया का स्थान लिया।
- As per the resolution of the **Urban Development Department of Gujarat**, he will assume charge **with immediate effect**.
- गुजरात के शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, वे तत्काल प्रभाव से पदभार ग्रहण करेंगे।

Ques: Which bank was fined ₹63.60 lakh by the Reserve Bank of India (RBI) for non-compliance with regulatory norms?

नियामकीय मानदंडों का पालन न करने पर RBI द्वारा ₹63.60 लाख का जुर्माना किस बैंक पर लगाया गया?

- A) Bank of Maharashtra / बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- B) DCB Bank / डीसीबी बैंक
- C) **CSB Bank / सीएसबी बैंक**
- D) Punjab & Sind Bank / पंजाब एंड सिंध बैंक
- E) Indian Overseas Bank / इंडियन ओवरसीज बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Reserve Bank of India imposed monetary penalties on **three banks** for non-

compliance with its regulatory guidelines.

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नियामकीय दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर तीन बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया।
- A fine of ₹32.50 lakh was imposed on Bank of Maharashtra.
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर ₹32.50 लाख का जुर्माना लगाया गया।
- A penalty of ₹29.60 lakh was imposed on DCB Bank.
- डीसीबी बैंक पर ₹29.60 लाख का जुर्माना लगाया गया।
- The highest penalty of ₹63.60 lakh was imposed on CSB Bank.
- सबसे अधिक ₹63.60 लाख का जुर्माना सीएसबी बैंक पर लगाया गया।
- The penalties were related to non-compliance with RBI's regulatory norms.
- ये सभी जुर्माने RBI के नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित थे।

Ques: Punjab National Bank (PNB) announced which themed half marathon to honour the Indian Armed Forces and promote fitness?

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मान देने और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए किस थीम आधारित हाफ मैराथन की घोषणा की?

- A) PNB Fit India Run / पीएनबी फिट इंडिया रन
- B) PNB Veer Run / पीएनबी वीर रन
- C) PNB Soldierathon 2026 / पीएनबी सोल्जरार्थॉन 2026
- D) PNB National Pride Marathon / पीएनबी नेशनल प्राइड मैराथन
- E) PNB Unity Run / पीएनबी यूनिटी रन

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Punjab National Bank (PNB) announced the 'PNB Soldierathon 2026', a themed half marathon, at its Corporate Office in Dwarka, New Delhi.
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने द्वारका, नई दिल्ली स्थित अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में

थीम आधारित हाफ मैराथन 'PNB सोल्जरार्थॉन 2026' की घोषणा की।

- The initiative aims to honour the Indian Armed Forces.
- इस पहल का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मान देना है।
- It also seeks to promote fitness and a healthy lifestyle among citizens.
- यह नागरिकों में फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने का भी प्रयास करती है।
- The event encourages discipline, national pride, and stronger community engagement.
- यह आयोजन अनुशासन, राष्ट्रीय गौरव और सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करता है।
- The Soldierathon is part of PNB's Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives and supports nation-building efforts.
- सोल्जरार्थॉन PNB की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहल का हिस्सा है और राष्ट्र निर्माण के प्रयासों का समर्थन करता है।

Ques: What did the Ministry of Finance state regarding Foreign Direct Investment (FDI) equity inflows into India's banking sector in FY 2024–25?

वित्त वर्ष 2024–25 में बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इक्विटी प्रवाह को लेकर वित्त मंत्रालय ने क्या कहा?

- A) It increased sharply compared to FY23 / FY23 की तुलना में इसमें तेज़ वृद्धि हुई
- B) It remained unchanged from FY23 / यह FY23 के समान ही रहा
- C) It declined significantly compared to FY23 / FY23 की तुलना में इसमें भारी गिरावट आई
- D) It crossed USD 1 billion / यह 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया
- E) Data was not disclosed / आंकड़े जारी नहीं किए गए

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- The Ministry of Finance stated that **FDI equity inflows into the banking sector declined to USD 115 million in FY 2024–25**, compared to **USD 898 million in FY 2022–23**.
- वित्त मंत्रालय के अनुसार, बैंकिंग क्षेत्र में **FDI इक्विटी प्रवाह FY 2024–25 में घटकर 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया**, जबकि **FY 2022–23 में यह 898 मिलियन डॉलर था**।
- FDI inflows include **equity inflow, equity capital of unincorporated bodies, re-invested earnings, and other capital**.
- FDI प्रवाह में **इक्विटी निवेश, अविनियमित निकायों की इक्विटी पूंजी, पुनर्निवेशित आय, और अन्य पूंजी शामिल होती है**।
- Among public sector banks, State Bank of India recorded the **highest foreign shareholding**.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में **भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में सबसे अधिक विदेशी शेयरधारिता दर्ज की गई**।
- This foreign shareholding includes investments from:
 - **Foreign Direct Investment (FDI) / प्रत्यक्ष विदेशी निवेश**
 - **Foreign Portfolio Investors / Foreign Institutional Investors (FPI/FII) / विदेशी पोर्टफोलियो/संस्थागत निवेशक**
 - **Non-Resident Indians (NRIs) / अनिवासी भारतीय**
- As per the Reserve Bank of India Master Directions on '*Acquisition and Holding of Shares or Voting Rights in Banking Companies*', **prior RBI approval is mandatory for acquiring 5% or more of the paid-up capital of a banking company**.
- **RBI के 'बैंकिंग कंपनियों में शेयर या मतदान अधिकारों के अधिग्रहण एवं धारण संबंधी मास्टर निर्देशों के अनुसार, किसी बैंक की चुकता पूंजी का 5% या उससे अधिक अधिग्रहण करने के लिए RBI की पूर्व अनुमति अनिवार्य है**।

Rankings with their foreign Shareholding :

- 1 State Bank of India - 11.07%
- 2 Canara Bank - 10.55%
- 3 Bank of Baroda - 9.43%

- 4 Union Bank of India - 7.48%
5 Punjab National Bank - 5.85%
-

Ques: According to a report by State Bank of India (SBI), what percentage of India's agricultural exports to the United States will now face zero tariff?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के अमेरिका को होने वाले कृषि निर्यात का कितना प्रतिशत अब शून्य शुल्क (Zero Tariff) का लाभ प्राप्त करेगा?

- A) 50%
B) 60%
C) 65%
D) 70%
E) 75%

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- According to a report by State Bank of India (SBI), nearly 75% of India's agricultural exports to the United States will now face zero tariff.
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका को भारत के लगभग 75% कृषि निर्यात पर अब शून्य शुल्क लगेगा।
- Agricultural products worth \$1.36 billion will get access to the US market with zero additional duty.
- \$1.36 अरब डॉलर मूल्य के कृषि उत्पादों को अमेरिका में बिना अतिरिक्त शुल्क के प्रवेश मिलेगा।
- Products worth \$1.035 billion are assured zero reciprocal tariff treatment.
- \$1.035 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों को शून्य पारस्परिक शुल्क (reciprocal tariff) की गारंटी दी गई है।
- This move strengthens India's agricultural trade surplus of around \$1.3 billion with the United States.
- यह कदम अमेरिका के साथ भारत के लगभग \$1.3 अरब के कृषि व्यापार अधिशेष को और मज़बूत करता है।

- The zero-tariff access is expected to improve price competitiveness and boost export volumes.
- शून्य शुल्क व्यवस्था से भारतीय उत्पादों की कीमत प्रतिस्पर्धा और निर्यात मात्रा में वृद्धि होने की उम्मीद है।

Major Beneficiary Sectors / प्रमुख लाभार्थी क्षेत्र:

Rice:

- US global rice imports stand at \$1.378 billion, with imports from India at \$341 million.
- The US rice import market share of India is 24.7%.
- चावल: अमेरिका का कुल चावल आयात \$1.378 अरब है, जिसमें भारत से \$341 मिलियन का आयात होता है और भारत की हिस्सेदारी 24.7% है।

Fishery Sector:

- US global imports of fish and aquatic invertebrates are valued at \$18.84 billion.
- Imports from India amount to \$1.8 billion, giving India a 9.6% share.
- मत्स्य क्षेत्र: अमेरिका का कुल आयात \$18.84 अरब है, जिसमें भारत से \$1.8 अरब का आयात होता है और हिस्सेदारी 9.6% है।

Tea, Coffee and Spices:

- US global imports are \$14.02 billion, with India exporting \$396 million.
- India's share stands at 2.8%.
- चाय, कॉफी और मसाले: अमेरिका का कुल आयात \$14.02 अरब है, जिसमें भारत से \$396 मिलियन का आयात होता है और हिस्सेदारी 2.8% है।

Overall Agricultural Trade Position / समग्र कृषि व्यापार स्थिति:

- Across selected categories, total US agricultural imports are \$81.95 billion.
- Imports from India amount to \$2.89 billion, giving India an overall share of 3.5%.
- चयनित श्रेणियों में अमेरिका का कुल कृषि आयात \$81.95 अरब है, जिसमें भारत से

\$2.89 अरब का आयात होता है और कुल हिस्सेदारी 3.5% है।

Ques: Which organization introduced a Braille-enabled Premier Credit Card to support visually impaired users in India?

दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए ब्रेल-सक्षम प्रीमियर क्रेडिट कार्ड किस संस्था ने पेश किया?

- A) State Bank of India (SBI) / भारतीय स्टेट बैंक
- B) Punjab National Bank (PNB) / पंजाब नेशनल बैंक
- C) BOBCARD Limited (Bank of Baroda) / बॉबकार्ड लिमिटेड (बैंक ऑफ बड़ौदा)
- D) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- E) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- BOBCARD Limited, the credit card arm of Bank of Baroda, introduced a Braille-enabled version of its Premier Credit Card at an event held in Manipal, Karnataka.
- बैंक ऑफ बड़ौदा की क्रेडिट कार्ड इकाई BOBCARD लिमिटेड ने कर्नाटक के मणिपाल में आयोजित कार्यक्रम में ब्रेल-सक्षम प्रीमियर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।
- The card incorporates Braille elements to help visually impaired users identify and use the card with greater ease and confidence during everyday transactions.
- इस कार्ड में ब्रेल चिह्न शामिल किए गए हैं, जिससे दृष्टिबाधित उपयोगकर्ता दैनिक लेन-देन में कार्ड को आसानी और आत्मविश्वास के साथ पहचान व उपयोग कर सकें।
- It also provides accelerated rewards on travel, lifestyle, dining, and international transactions.
- इसमें यात्रा, लाइफस्टाइल, डाइनिंग और अंतरराष्ट्रीय लेन-देन पर तेज़ रिवॉईस मिलते हैं।

- The card offers travel benefits, including complimentary domestic airport lounge access and curated lifestyle privileges.
- कार्ड में घरेलू हवाई अड्डों के लाउंज की निःशुल्क सुविधा और विशेष लाइफस्टाइल लाभ भी शामिल हैं।

Braille-Enabled Card Providers in India | भारत में ब्रेल-सक्षम कार्ड प्रदाता

- Punjab National Bank (PNB)
 - PNB Braille Credit Card (Credit Card)
 - First major bank to launch a dedicated Braille Credit Card (December 2025).
 - ब्रेल-सक्षम समर्पित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला बड़ा बैंक।
- BOBCARD Limited / Bank of Baroda
 - bob inSIGHT Debit Card (Debit Card)
 - Features tactile dots and a rounded notch for orientation.
 - पहचान हेतु स्पर्शनीय डॉट्स और राउंडेड नॉच की सुविधा।
- State Bank of India (SBI)
 - Braille Debit Card (Debit Card)
 - Provides Braille-enabled cards on request for visually impaired account holders.
 - दृष्टिबाधित खाताधारकों को अनुरोध पर ब्रेल-सक्षम कार्ड उपलब्ध कराता है।

Ques: What was the year-on-year (YoY) growth in Currency in Circulation (CiC) in January 2026?

जनवरी 2026 में प्रचलन में मुद्रा (CiC) की साल-दर-साल (YoY) वृद्धि कितनी रही?

- A) 5.3%
- B) 8.5%
- C) 9.7%
- D) 11.1%
- E) 14.4%

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या :

- **Currency in Circulation (CiC)** touched a **record high of ₹40 lakh crore** for the month ending **January 2026**.
- **जनवरी 2026** को समाप्त माह में प्रचलन में मुद्रा (CiC) ₹40 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई।
- CiC registered a **year-on-year growth of 11.1%**, significantly higher than **5.3%** recorded in January last year.
- CiC में **11.1% की साल-दर-साल वृद्धि** दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी माह यह **5.3%** थी।
- On a **year-to-date (YTD)** basis, CiC increased by **₹2.76 lakh crore**, which is about **3.11 times higher** than the increase during the same period last year.
- **वर्ष-से-तारीख (YTD)** आधार पर CiC में ₹2.76 लाख करोड़ की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से लगभग **3.11 गुना अधिक** है।
- Despite the rise in cash usage, the **cash-to-GDP ratio declined to 11% in FY26 (so far)**, compared to **14.4% in FY21**, indicating deeper financialisation and digital payments penetration.
- नकदी प्रचलन बढ़ने के बावजूद, **FY26 (अब तक)** में **नकद-से-GDP अनुपात घटकर 11%** रह गया, जो **FY21 में 14.4%** था।
- These findings were reported by SBI Research.
- यह आँकड़े SBI Research द्वारा जारी किए गए हैं।

Ques: Who released the latest edition of “Trade Watch Quarterly” for Q2 FY 2025–26 (July–September 2025)? Q2 FY 2025–26 (जुलाई–सितंबर 2025) के लिए “ट्रेड वॉच क्वार्टरली” का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया?

- A) Amitabh Kant / अमिताभ कांत
- B) Rajiv Kumar / राजीव कुमार
- C) Suman Bery / सुमन बेरी
- D) Sanjeev Sanyal / संजीव सान्याल
- E) Arvind Panagariya / अरविंद पनगढ़िया

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The latest edition of “Trade Watch Quarterly” for Q2 FY 2025–26 was released by Suman Bery, Vice-Chairman of NITI Aayog.
- Q2 FY 2025–26 के लिए “ट्रेड वॉच क्वार्टरली” का नवीनतम संस्करण नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी किया गया।
- The report notes that global trade growth has moderated but remains positive, with services trade outperforming goods trade.
- रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार वृद्धि धीमी हुई है, लेकिन सकारात्मक बनी हुई है, जहाँ सेवा व्यापार वस्तु व्यापार से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।
- India’s trade expansion in Q2 FY26 was driven by export-led momentum, with services and merchandise exports growing by around 8.5%, faster than imports.
- Q2 FY26 में भारत का व्यापार विस्तार निर्यात-आधारित गति से संचालित रहा, जहाँ सेवा और वस्तु निर्यात लगभग 8.5% बढ़े, जो आयात वृद्धि से अधिक था।
- The report highlights India’s increasing alignment with regional value chains and new trade corridors.
- रिपोर्ट में क्षेत्रीय वैल्यू चेन और नए व्यापार गलियारों के साथ भारत के बढ़ते एकीकरण पर प्रकाश डाला गया है।
- E-commerce exports, though currently modest, are projected to contribute 20–30% of India’s merchandise exports by 2030.
- ई-कॉमर्स निर्यात वर्तमान में सीमित हैं, लेकिन 2030 तक भारत के वस्तु निर्यात में 20–30% योगदान देने का अनुमान है।
- Electronics exports grew nearly fivefold between 2016 and 2024 to reach USD 42.1 billion, with India’s global electronics demand share growing at a CAGR of 17.2%, far above the global average of 4.4%.
- 2016 से 2024 के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग पाँच गुना बढ़कर 42.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मांग में भारत की हिस्सेदारी 17.2% CAGR से बढ़ी, जो वैश्विक औसत 4.4% से कहीं अधिक है।

Ques: NPCI extended the 'UPI One World' wallet service for international visitors attending which event?

NPCI ने 'UPI One World' वॉलेट सेवा का विस्तार किस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के लिए किया?

- A) G20 Summit 2026 / G20 शिखर सम्मेलन 2026
- B) India AI Impact Summit 2026 / इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026
- C) Digital India Conference 2026 / डिजिटल इंडिया सम्मेलन 2026
- D) Vibrant Gujarat Summit 2026 / वाइब्रेंट गुजरात समिट 2026
- E) World Economic Forum 2026 / वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या :

- National Payments Corporation of India (NPCI) has extended the **'UPI One World' wallet service for international visitors from 40+ countries.**
- National Payments Corporation of India (NPCI) ने **40 से अधिक देशों के अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के लिए 'UPI One World' वॉलेट सेवा का विस्तार किया है।**
- This facility is specifically available for attendees of the **India AI Impact Summit 2026, held from 16–20 February 2026 in New Delhi.**
- यह सुविधा **16–20 फरवरी 2026 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित India AI Impact Summit 2026 में भाग लेने वाले आगंतुकों के लिए उपलब्ध है।**
- Under this **pilot initiative**, foreign travellers can make **seamless, secure, real-time Person-to-Merchant (P2M) payments** using UPI while staying in India.
- इस **पायलट पहल** के तहत विदेशी यात्री भारत में रहते हुए **सहज, सुरक्षित और रियल-टाइम Person-to-Merchant (P2M) UPI भुगतान** कर सकते हैं।
- The initiative aims to **promote digital payments, showcase India's fintech leadership, and enhance convenience for inbound tourists and global delegates.**
- इस पहल का उद्देश्य **डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, भारत की फिनटेक क्षमता को प्रदर्शित करना और विदेशी पर्यटकों व वैश्विक प्रतिनिधियों की सुविधा बढ़ाना है।**

Ques: The Reserve Bank of India (RBI) granted final approval to Bain Capital affiliates to acquire joint control and up to what percentage stake in Manappuram Finance?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बेन कैपिटल की सहयोगी कंपनियों को मणप्पुरम फाइनेंस में संयुक्त नियंत्रण और अधिकतम कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने की अंतिम मंजूरी दी?

- A) 26%
- B) 33%
- C) 41.66%
- D) 49%
- E) 51%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India has granted final approval to affiliates of Bain Capital to acquire joint control and up to 41.66% stake in Kerala-based Manappuram Finance.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने बेन कैपिटल की सहयोगी कंपनियों को केरल स्थित मणप्पुरम फाइनेंस में संयुक्त नियंत्रण और अधिकतम 41.66% हिस्सेदारी हासिल करने की अंतिम मंजूरी दी है।
- This approval clears the way for the completion of Bain Capital's ₹4,385 crore investment in the gold loan-focused NBFC.
- इस मंजूरी से गोल्ड लोन पर केंद्रित NBFC में बेन कैपिटल के ₹4,385 करोड़ के निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- Bain Capital was founded in 1984 and is headquartered in Boston, Massachusetts, USA.
- बेन कैपिटल की स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय बोस्टन, मैसाचुसेट्स, अमेरिका में स्थित है।
- Manappuram Finance was originally founded in 1949 and is headquartered at Valapad in the Thrissur district of Kerala.

- मणप्पुरम फाइनेंस की मूल स्थापना 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय केरल के त्रिशूर ज़िले के वलापाड में स्थित है।
- It is a Non-Deposit Accepting Loan Company and is classified as a Systemically Important Non-Banking Financial Company (NBFC-ND-SI).
- यह एक गैर-जमा स्वीकार करने वाली ऋण कंपनी है और इसे प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC-ND-SI) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- Deepak Reddy assumed charge as the Chief Executive Officer (CEO) of Manappuram Finance on August 1, 2025.
- दीपक रेड्डी ने 1 अगस्त 2025 को मणप्पुरम फाइनेंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पदभार संभाला।

Ques: NPCI has partnered with which company to advance its sovereign AI model for digital payments?

NPCI ने डिजिटल भुगतान के लिए सॉवरेन AI मॉडल को आगे बढ़ाने हेतु किस कंपनी के साथ साझेदारी की है?

- A) Nvidia / एनवीडिया
- B) Google / गूगल
- C) Microsoft / माइक्रोसॉफ्ट
- D) IBM / आईबीएम
- E) Amazon / अमेज़न

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या :

- National Payments Corporation of India (NPCI) has partnered with Nvidia to scale and advance a sovereign AI model for India's digital payments ecosystem.
- NPCI ने भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम के लिए सॉवरेन AI मॉडल को विकसित और विस्तारित करने हेतु Nvidia के साथ साझेदारी की है।
- The initiative focuses on building AI capabilities aligned with India's

regulatory framework and data sovereignty requirements.

- यह पहल भारत की नियामकीय व्यवस्था और डेटा संप्रभुता आवश्यकताओं के अनुरूप AI क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित है।
- NPCI will leverage Nvidia's advanced AI and accelerated computing platforms, including Nvidia Nemotron models.
- NPCI, Nvidia के उन्नत AI और accelerated computing प्लेटफॉर्म, जैसे Nvidia Nemotron मॉडल्स, का उपयोग करेगा।
- The collaboration aims to enhance trust, resilience, security, and efficiency in large-scale real-time payment systems.
- इस सहयोग का उद्देश्य बड़े पैमाने पर रियल-टाइम भुगतान प्रणालियों में भरोसा, लचीलापन, सुरक्षा और दक्षता को मजबूत करना है।

Ques: What key change has the Reserve Bank of India (RBI) introduced regarding Default Loss Guarantees (DLGs) for non-bank lenders?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंक ऋणदाताओं के लिए डिफॉल्ट लॉस गारंटी (DLG) को लेकर कौन-सा प्रमुख बदलाव किया है?

- A) Banned the use of DLGs permanently / DLG के उपयोग पर स्थायी प्रतिबंध लगाया
- B) Allowed DLGs only for banks, not NBFCs / DLG केवल बैंकों के लिए अनुमति दी, NBFCs के लिए नहीं
- C) Restored the use of DLGs for NBFCs in loan loss provisioning / NBFCs को ऋण हानि प्रावधान में DLG शामिल करने की अनुमति दी
- D) Increased the cap on DLGs to 10% of loan portfolio / DLG की सीमा 10% तक बढ़ाई
- E) Allowed DLGs only for government-backed fintechs / DLG केवल सरकारी समर्थित फिनटेक्स के लिए अनुमति दी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has restored the use of Default Loss Guarantees (DLGs) for non-bank lenders, reversing its curbs imposed in May 2025.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मई 2025 में लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेते हुए गैर-बैंक ऋणदाताओं के लिए डिफॉल्ट लॉस गारंटी (DLG) के उपयोग को बहाल कर दिया है।
- Under the revised framework, NBFCs can again factor in DLGs while calculating loan loss provisions, and the changes take effect immediately.
- संशोधित ढांचे के तहत NBFCs अब ऋण हानि प्रावधान की गणना में DLG को शामिल कर सकती हैं और यह व्यवस्था तुरंत प्रभावी होगी।
- The guarantee must be an integral part of the loan arrangement and cannot be treated as a separate standalone protection.
- यह गारंटी ऋण व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए और इसे अलग सुरक्षा के रूप में नहीं माना जाएगा।
- Loss estimates must be updated every time the DLG is invoked, as the level of protection reduces with each utilisation.
- प्रत्येक बार DLG के उपयोग पर हानि अनुमान को अपडेट करना होगा, क्योंकि हर उपयोग के साथ सुरक्षा घटती जाती है।
- DLGs are risk-sharing mechanisms widely used in digital lending and co-lending models, usually capped at 5% of the loan portfolio and often backed by fixed deposits from fintech partners.
- DLG जोखिम-साझाकरण तंत्र हैं, जो डिजिटल लेंडिंग और सह-ऋण मॉडल में सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं, आमतौर पर ऋण पोर्टफोलियो के 5% तक सीमित होते हैं और अक्सर फिनटेक भागीदारों की फिक्स्ड डिपॉजिट से समर्थित होते हैं।
- Earlier, in May 2025, RBI had required NBFCs to exclude fintech-provided DLGs from provisioning calculations, leading to higher credit costs and reduced profitability.
- इससे पहले मई 2025 में RBI ने NBFCs को प्रावधान गणना से फिनटेक-प्रदत्त DLG को बाहर रखने का निर्देश दिया था, जिससे क्रेडिट लागत बढ़ी और लाभप्रदता में गिरावट आई थी।

Ques: Why has SEBI constituted a working group recently?

SEBI ने हाल ही में कार्यसमूह क्यों गठित किया है?

- A) To regulate cryptocurrency exchanges / क्रिप्टोकॉरेंसी एक्सचेंज को विनियमित करने के लिए
- B) To review the framework for ESG Rating Providers / ESG रेटिंग प्रदाताओं के ढांचे की समीक्षा के लिए
- C) To revise mutual fund taxation rules / म्यूचुअल फंड कर नियमों में संशोधन के लिए
- D) To promote IPO listings / IPO लिस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए
- E) To regulate commodity markets / क्मोडिटी बाजार को विनियमित करने के लिए

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या :

- Securities and Exchange Board of India (SEBI) has constituted a dedicated working group to review the regulatory framework for ESG Rating Providers (ERPs).
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने ESG रेटिंग प्रदाताओं (ERPs) के नियामक ढांचे की समीक्षा के लिए एक विशेष कार्यसमूह का गठन किया है।
- The move follows feedback from market participants regarding ESG rating practices.
- यह कदम बाजार सहभागियों से प्राप्त फीडबैक के बाद उठाया गया है।
- The panel includes representatives from issuers, investors, domestic & global ERPs, ESG analysts, legal experts, and academia.
- इस पैनल में इश्यूअर्स, निवेशकों, घरेलू व वैश्विक ERPs, ESG विश्लेषकों, कानूनी विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- The group will review existing regulations, assess global developments, and recommend measures to enhance transparency and reliability in ESG ratings.
- यह कार्यसमूह मौजूदा नियमों की समीक्षा करेगा, वैश्विक विकास का आकलन करेगा और ESG रेटिंग में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के उपाय सुझाएगा।

Ques: Indian Overseas Bank (IOB) expanded its start-up focused banking network by launching exclusive branches in which cities?

इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने स्टार्ट-अप केंद्रित बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार किन शहरों में विशेष शाखाएँ शुरू करके किया?

- A) Chennai, Hyderabad, Pune / चेन्नई, हैदराबाद, पुणे
- B) Delhi, Mumbai, Bengaluru / दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु
- C) Kolkata, Ahmedabad, Jaipur / कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर
- D) Kochi, Trivandrum, Coimbatore / कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कोयंबटूर
- E) Noida, Gurugram, Faridabad / नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Indian Overseas Bank has expanded its dedicated Start-up Banking Network by launching exclusive start-up focused branches in Delhi, Mumbai, and Bengaluru.
- इंडियन ओवरसीज बैंक ने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में विशेष स्टार्ट-अप केंद्रित शाखाएँ शुरू करके अपने स्टार्ट-अप बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार किया है।
- This expansion builds on the success of its first start-up focused branch in Chennai, which was launched in June 2024.
- यह विस्तार जून 2024 में चेन्नई में शुरू की गई पहली स्टार्ट-अप शाखा की सफलता पर आधारित है।
- The initiative was announced on the occasion of the 90th Foundation Day of Indian Overseas Bank.
- यह पहल इंडियन ओवरसीज बैंक के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर घोषित की गई।
- These specialised branches offer a tailored Startup Current Account with benefits such as waiver of Quarterly Average Balance (QAB) for the first 18 months.
- इन विशेष शाखाओं में स्टार्ट-अप्स के लिए विशेष करंट अकाउंट उपलब्ध है, जिसमें

पहले 18 महीनों तक तिमाही औसत शेष राशि (QAB) से छूट दी गई है।

- Additional features include 200 free cheque leaves per month and free NEFT, RTGS, and IMPS transactions.

- अतिरिक्त सुविधाओं में प्रति माह 200 निःशुल्क चेक पत्ते और निःशुल्क NEFT, RTGS तथा IMPS लेन-देन शामिल हैं।

- The bank also launched 'IOB Gram Sweekar', a rural outreach programme aimed at strengthening credit delivery, enhancing financial literacy, and ensuring universal access to flagship banking products.

- बैंक ने 'IOB ग्राम स्वीकर' नामक ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य ऋण वितरण को मजबूत करना, वित्तीय साक्षरता बढ़ाना और प्रमुख बैंकिंग उत्पादों तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना है।

- Under this initiative, IOB has adopted 90 Gram Panchayats across 14 districts in Tamil Nadu and Kerala.

- इस पहल के तहत IOB ने तमिलनाडु और केरल के 14 ज़िलों में 90 ग्राम पंचायतों को गोद लिया है।

Ques: What is the key impact of the Reserve Bank of India's (RBI) new lending norms for capital market intermediaries effective from April 1?

1 अप्रैल से प्रभावी RBI के नए ऋण नियमों का पूंजी बाजार मध्यस्थों पर क्या प्रमुख प्रभाव पड़ेगा?

A) Banks can freely lend for brokers' proprietary trading / बैंक ब्रोकरों के स्वयं के ट्रेडिंग के लिए स्वतंत्र रूप से ऋण दे सकेंगे

B) Unsecured loans to stock brokers are permitted / स्टॉक ब्रोकरों को बिना गारंटी ऋण देने की अनुमति होगी

C) All credit to securities firms must be fully collateral-backed / प्रतिभूति कंपनियों को दिया गया हर ऋण पूरी तरह जमानत-आधारित होगा

D) Bank guarantees for proprietary trades need no cash collateral / प्रोप्राइटरी ट्रेड के लिए बैंक गारंटी में नकद जमानत की आवश्यकता नहीं होगी

E) Commodity brokers are exempted from the new norms / क्मोडिटी ब्रोकरों को

नए नियमों से छूट दी गई है

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has tightened lending norms for capital market intermediaries, including stock and commodity brokers involved in proprietary trading.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में लगे स्टॉक और क्मोडिटी ब्रोकर्स सहित पूंजी बाजार मध्यस्थों के लिए ऋण नियम सख्त कर दिए हैं।
- Under the new prudential framework, all loans to securities firms must be fully backed by collateral, eliminating unsecured exposure to speculative activities.
- नए सावधानीपूर्ण ढांचे के तहत प्रतिभूति कंपनियों को दिया गया प्रत्येक ऋण पूरी तरह जमानत से सुरक्षित होना अनिवार्य होगा, जिससे सट्टात्मक गतिविधियों में बिना गारंटी जोखिम समाप्त होगा।
- Banks are prohibited from lending for brokers' own-account (proprietary) trading or for investments made by brokers.
- बैंकों को ब्रोकर्स की स्वयं की ट्रेडिंग या उनके निवेश के लिए ऋण देने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- Bank guarantees issued for proprietary trades must be fully secured, with at least 50% collateral in cash and the remaining portion in cash equivalents or government securities.
- प्रोप्राइटरी ट्रेड के लिए जारी बैंक गारंटी पूरी तरह सुरक्षित होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 50% जमानत नकद में और शेष नकद समकक्ष या सरकारी प्रतिभूतियों में हो।
- These measures aim to curb excessive risk-taking by capital market intermediaries and strengthen financial stability.
- इन उपायों का उद्देश्य पूंजी बाजार मध्यस्थों द्वारा अत्यधिक जोखिम लेने पर रोक लगाना और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना है।

Ques: From which date are bank loans to the National Cooperative Development Corporation (NCDC) for on-lending to cooperative societies eligible for Priority Sector Lending (PSL) classification?

किस तिथि से सहकारी समितियों को ऑन-लेंडिंग के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के रूप में वर्गीकृत किया गया है?

- A) 1 April 2025 / 1 अप्रैल 2025
- B) 1 July 2025 / 1 जुलाई 2025
- C) 19 January 2026 / 19 जनवरी 2026
- D) 1 April 2026 / 1 अप्रैल 2026
- E) 26 January 2026 / 26 जनवरी 2026

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India, in consultation with the Government of India, announced that loans sanctioned by banks to the National Cooperative Development Corporation for on-lending to cooperative societies will be eligible for Priority Sector Lending classification with effect from 19 January 2026.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से यह घोषणा की कि सहकारी समितियों को ऑन-लेंडिंग के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को बैंकों द्वारा दिए गए ऋण 19 जनवरी 2026 से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में मान्य होंगे।
- This PSL classification applies to banks other than Regional Rural Banks, Urban Cooperative Banks, Small Finance Banks, and Local Area Banks.
- यह प्राथमिकता क्षेत्र वर्गीकरण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों और लोकल एरिया बैंकों पर लागू नहीं होगा।
- Urban Cooperative Banks have been permitted to open new branches, and their housing loan limit has been enhanced from 10% to 25% of total loans and advances.
- शहरी सहकारी बैंकों को नई शाखाएँ खोलने की अनुमति दी गई है तथा उनके आवास

ऋण की सीमा कुल ऋण एवं अग्रिमों के 10% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है।

- The Banking Regulation Act has been amended to increase the tenure of directors of Cooperative Banks from 8 years to 10 years.
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन कर सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।
- The National Urban Co-operative Finance and Development Corporation Limited has been established as an umbrella organisation for Urban Cooperative Banks to provide IT infrastructure and operational support.
- शहरी सहकारी बैंकों के लिए आईटी अवसंरचना और परिचालन सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है।
- A Shared Services Entity named Sahakar Sarthi has been set up to provide technological services to Rural Cooperative Banks, and these banks have been included under the Integrated Ombudsman Scheme of RBI.
- ग्रामीण सहकारी बैंकों को तकनीकी सेवाएँ देने के लिए 'सहकार सारथी' नामक साझा सेवा इकाई स्थापित की गई है तथा इन्हें RBI की एकीकृत लोकपाल योजना में शामिल किया गया है।

Ques : RBI has deferred implementation of Unique Transaction Identifier (UTI) for OTC derivatives till which date?

RBI ने OTC डेरिवेटिव्स के लिए UTI लागू करने की समयसीमा किस तिथि तक टाली है?

- A) January 1, 2026 / 1 जनवरी 2026
- B) July 1, 2026 / 1 जुलाई 2026
- C) January 1, 2027 / 1 जनवरी 2027
- D) March 31, 2027 / 31 मार्च 2027
- E) December 31, 2026 / 31 दिसंबर 2026

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has deferred the implementation of the Unique Transaction Identifier (UTI) for all Over-the-Counter (OTC) derivatives to January 1, 2027.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी OTC डेरिवेटिव्स के लिए यूनिक ट्रांज़ैक्शन आईडी (UTI) लागू करने की समयसीमा 1 जनवरी 2027 तक बढ़ा दी है।
- The UTI system will help regulators obtain a comprehensive view of the OTC derivatives market and enhance transparency.
- UTI प्रणाली से नियामकों को OTC डेरिवेटिव्स बाजार की समग्र जानकारी प्राप्त होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
- The mandate will apply to transactions entered into on or after January 1, 2027.
- यह अनिवार्यता 1 जनवरी 2027 या उसके बाद किए गए लेनदेन पर लागू होगी।
- Currently, OTC transactions are reported to the Trade Repository managed by Clearing Corporation of India Limited (CCIL-TR).
- वर्तमान में OTC लेनदेन की रिपोर्टिंग Clearing Corporation of India Limited (CCIL-TR) द्वारा संचालित ट्रेड रिपॉजिटरी में की जाती है।
- Covered instruments include rupee interest rate derivatives, forward contracts in government securities, foreign currency derivatives, foreign currency interest rate derivatives, and credit derivatives.
- इसमें रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स, सरकारी प्रतिभूतियों में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स, विदेशी मुद्रा ब्याज दर डेरिवेटिव्स और क्रेडिट डेरिवेटिव्स शामिल हैं।

Ques: DBS Bank Limited partnered with Visa to pilot agent-initiated payments under which innovative payment framework?

डीबीएस बैंक लिमिटेड ने एजेंट-इनिशिएटेड पेमेंट्स के पायलट के लिए वीज़ा के साथ किस नवोन्मेषी भुगतान ढांचे के तहत साझेदारी की है?

- A) Visa Secure Pay / वीज़ा सिक्क्योर पे
- B) Visa Token Service / वीज़ा टोकन सेवा
- C) Visa Intelligent Commerce (VIC) / वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स
- D) Visa Direct / वीज़ा डायरेक्ट
- E) Visa PayWave AI / वीज़ा पेवेव एआई

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- DBS Bank Limited, Southeast Asia's largest lender, entered into a strategic partnership with Visa to pilot agent-initiated payments under Visa Intelligent Commerce (VIC).
- दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे बड़े बैंक DBS बैंक लिमिटेड ने वीज़ा के साथ Visa Intelligent Commerce (VIC) के तहत एजेंट-इनिशिएटेड भुगतान के पायलट के लिए रणनीतिक साझेदारी की।
- With this initiative, DBS became the first issuer in the Asia-Pacific region to operationalise real-world agentic commerce use cases.
- इस पहल के साथ DBS एशिया-प्रशांत क्षेत्र का पहला जारीकर्ता बना जिसने वास्तविक दुनिया में एजेंटिक कॉमर्स उपयोग-मामलों को लागू किया।
- Visa Intelligent Commerce (VIC) is a payment framework that enables AI agents to securely initiate and complete transactions on behalf of consumers.
- Visa Intelligent Commerce (VIC) एक भुगतान ढांचा है जो उपभोक्ताओं की ओर से AI एजेंट्स को सुरक्षित रूप से लेन-देन शुरू करने और पूरा करने में सक्षम बनाता है।
- Under the pilot, AI agents completed food and beverage purchases using DBS/POSB credit and debit cards, with payments processed through secure, issuer-approved flows.
- इस पायलट के तहत AI एजेंट्स ने DBS/POSB क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग करके खाद्य एवं पेय पदार्थों की खरीद की, जिनके भुगतान सुरक्षित और जारीकर्ता-स्वीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से किए गए।
- Explicit customer consent was maintained throughout the transactions.
- पूरे लेन-देन के दौरान ग्राहक की स्पष्ट सहमति सुनिश्चित की गई।

Ques: What is FiMI launched by NPCI?

NPCI द्वारा लॉन्च किया गया FiMI क्या है?

- A) A new UPI payment app / एक नया UPI पेमेंट ऐप
- B) A blockchain-based settlement system / ब्लॉकचेन आधारित सेटलमेंट सिस्टम
- C) A domain-specific AI language model for payments / भुगतान प्रणाली के लिए डोमेन-विशिष्ट AI भाषा मॉडल
- D) A new digital wallet / एक नया डिजिटल वॉलेट
- E) A credit scoring platform / एक क्रेडिट स्कोरिंग प्लेटफॉर्म

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- National Payments Corporation of India (NPCI) launched FiMI (Finance Model for India) at the India–AI Impact Summit 2026.
- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने India–AI Impact Summit 2026 में FiMI (फाइनेंस मॉडल फॉर इंडिया) लॉन्च किया।
- FiMI is a domain-specific language model built specifically for India's payments ecosystem.
- FiMI एक डोमेन-विशिष्ट भाषा मॉडल है, जिसे भारत की भुगतान प्रणाली के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है।
- Developed in-house by NPCI, it addresses limitations of general-purpose LLMs in high-scale, high-trust payment workflows.
- इसे NPCI ने इन-हाउस विकसित किया है और यह सामान्य LLMs की सीमाओं को दूर करता है, खासकर उच्च-स्तरीय और भरोसेमंद भुगतान प्रक्रियाओं में।
- FiMI currently powers NPCI's UPI Help Assistant, an AI-powered conversational support system for UPI users.
- FiMI वर्तमान में NPCI के UPI हेल्प असिस्टेंट को संचालित करता है, जो UPI उपयोगकर्ताओं के लिए AI आधारित संवादात्मक सहायता प्रणाली है।
- It supports transaction dispute handling, mandate lifecycle management, and regulatory queries.
- यह लेन-देन विवाद समाधान, मंडेट प्रबंधन और नियामकीय प्रश्नों का समाधान

करता है।

- The assistant currently supports English, Hindi, Telugu, and Bengali.
- यह असिस्टेंट वर्तमान में अंग्रेज़ी, हिंदी, तेलुगु और बंगाली भाषाओं का समर्थन करता है।
- Additional Indian languages will be added in the next 6–8 months to improve accessibility.
- अगले 6–8 महीनों में अन्य भारतीय भाषाएँ भी जोड़ी जाएंगी ताकि पहुंच बढ़ाई जा सके।

Ques: Which entity received RBI approval to acquire up to 9.95% stake in eight Indian banks?

किस संस्था को आठ भारतीय बैंकों में 9.95% तक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए RBI की मंजूरी मिली?

- A) HDFC Asset Management Company / एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी
- B) SBI Mutual Fund / एसबीआई म्यूचुअल फंड
- C) ICICI Prudential Asset Management Company / आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी
- D) Axis Asset Management Company / एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी
- E) Kotak Mahindra Asset Management Company / कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- ICICI Prudential Asset Management Company, along with group entities of ICICI Bank, received approval from the Reserve Bank of India to acquire up to 9.95% of the paid-up share capital or voting rights in eight Indian banks.
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी को आईसीआईसीआई बैंक समूह की इकाइयों के साथ आठ भारतीय बैंकों में 9.95% तक चुकता शेयर पूंजी या मतदान

अधिकार प्राप्त करने के लिए RBI की मंजूरी मिली।

- The banks covered under this approval are Bandhan Bank, City Union Bank, Equitas Small Finance Bank, Federal Bank, IDFC First Bank, HDFC Bank, Karur Vysya Bank, and RBL Bank.
- इस मंजूरी के तहत बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, करूर वैश्य बैंक और RBL बैंक शामिल हैं।
- The approval is valid for one year and requires completion of major shareholding within this period.
- यह मंजूरी एक वर्ष के लिए वैध है और इस अवधि में प्रमुख हिस्सेदारी पूरी करनी होगी।
- The aggregate holding must remain below 9.95% at all times.
- कुल हिस्सेदारी हर समय 9.95% से कम रखनी होगी।
- If the stake falls below 5% and is later increased again, fresh approval from RBI will be mandatory.
- यदि हिस्सेदारी 5% से नीचे गिरती है और बाद में फिर बढ़ाई जाती है, तो RBI से नई मंजूरी लेना अनिवार्य होगा

Ques: What is the minimum FD amount required to obtain IDFC First Bank's Hello Cashback Credit Card?

IDFC फर्स्ट बैंक के हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए न्यूनतम FD राशि कितनी है?

- A) ₹5,000
- B) ₹10,000
- C) ₹15,000
- D) ₹25,000
- E) ₹50,000

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- IDFC First Bank has launched the Hello Cashback Credit Card, an FD-backed credit card.
- आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जो FD-आधारित

क्रेडिट कार्ड है।

- The card is aimed at first-time users and customers with no credit history.
- यह कार्ड पहली बार क्रेडिट लेने वाले और बिना क्रेडिट हिस्ट्री वाले ग्राहकों के लिए बनाया गया है।
- Customers need to open a minimum FD of ₹10,000 to get the card.
- ग्राहकों को कार्ड प्राप्त करने के लिए कम से कम ₹10,000 की FD खोलनी होगी।
- The credit limit is 100% of the FD amount.
- क्रेडिट लिमिट FD राशि का 100% होगी।
- The card is issued on the RuPay network.
- यह कार्ड RuPay नेटवर्क पर जारी किया गया है।
- Founded: October 2015 | Headquarters: Mumbai | CEO: V. Vaidyanathan.
- स्थापना: अक्टूबर 2015 | मुख्यालय: मुंबई | सीईओ: वी. वैद्यनाथन।

Ques: What was India's factory-gate inflation (Wholesale Price Index – WPI) in January 2026, as per data released by the Ministry of Commerce and Industry?

जनवरी 2026 में भारत की फैक्ट्री-गेट महंगाई (थोक मूल्य सूचकांक – WPI) कितनी रही, जैसा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया?

- A) 0.95%
- B) 1.25%
- C) 1.81%
- D) 2.40%
- E) 3.20%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- India's factory-gate inflation, measured by the Wholesale Price Index (WPI), rose to 1.81% in January 2026, marking a 10-month high.
- भारत की फैक्ट्री-गेट महंगाई, जिसे थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से मापा जाता है, जनवरी 2026 में बढ़कर 1.81% हो गई, जो 10 महीनों का उच्चतम स्तर है।

- The data was released by the Ministry of Commerce and Industry.
- यह आंकड़े वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए।
- The rise in WPI inflation was mainly driven by:
 - Pickup in food prices
 - Sharp increase in core inflation
- WPI में वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य कीमतों में तेजी और कोर महंगाई में तीव्र बढ़ोतरी रही।
- Food inflation increased to 1.4% in January 2026, after remaining flat on a year-on-year basis in December 2025.
- खाद्य महंगाई दिसंबर 2025 में स्थिर रहने के बाद जनवरी 2026 में बढ़कर 1.4% हो गई।
- Core inflation (excluding food and fuel) rose sharply to 3.2% in January 2026.
- कोर महंगाई (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) जनवरी 2026 में तेजी से बढ़कर 3.2% हो गई।
- The current WPI base year is 2011–12, and the upcoming GDP series with base year 2022–23 will continue to use the existing WPI as deflators.
- वर्तमान WPI का आधार वर्ष 2011–12 है और आगामी 2022–23 आधार वर्ष वाली GDP श्रृंखला में भी WPI को डिफ्लेटर के रूप में उपयोग किया जाएगा।